

EXAM GENIUS

Presents

GENIUS CURRENT AFFAIRS

In Bilingual

27 March 2026



Achieve Success with Exam Genius - Your Ultimate Guide to Reasoning Mastery !



Ques: SEBI has partnered with which company to introduce verified badges for trading apps?

प्रश्न: ट्रेडिंग ऐप्स के लिए वेरिफाइड बैज शुरू करने हेतु सेबी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है?

- A) Microsoft / माइक्रोसॉफ्ट
- B) Amazon / अमेज़न
- C) Google / गूगल
- D) Meta / मेटा
- E) Apple / एप्पल

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Securities and Exchange Board of India has partnered with Google to tackle fraudulent trading apps.
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स से निपटने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है।
- A "Verified Tick Mark Badge" will be introduced for legitimate stock trading apps.
- वैध ट्रेडिंग ऐप्स के लिए "वेरिफाइड टिक मार्क बैज" शुरू किया जाएगा।
- The badge will appear on apps of registered stockbrokers/intermediaries on the Play Store.
- यह बैज प्ले स्टोर पर पंजीकृत स्टॉकब्रोकर/इंटरमीडियरीज के ऐप्स पर दिखाई देगा।
- The initiative aims to protect investors from fraud and scam apps.
- इसका उद्देश्य निवेशकों को फर्जी और धोखाधड़ी वाले ऐप्स से बचाना है।
- Google will use AI technology to identify and remove rule-violating apps and influencers.
- गूगल AI तकनीक का उपयोग करके नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐप्स और इन्फ्लुएंसर्स को हटाएगा।





Recent News Headlines Related to SEBI

- Securities and Exchange Board of India has reduced the minimum investment limit in Social Impact Funds (SIFs) from ₹2 lakh to ₹1,000.
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सोशल इम्पैक्ट फंड्स (SIFs) में न्यूनतम निवेश सीमा ₹2 लाख से घटाकर ₹1,000 कर दी है।
- Securities and Exchange Board of India (SEBI) has proposed changes to simplify nomination rules for demat accounts and mutual fund folios.
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो के नामांकन नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव दिया है।
- SEBI has formed a high-level expert working group. The group will prepare short-term and long-term technology roadmaps for India's securities market ecosystem. It is chaired by D. B. Phatak, Professor Emeritus at IIT Bombay.
- SEBI ने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कार्य समूह का गठन किया है। यह समूह भारत के प्रतिभूति बाजार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रौद्योगिकी रोडमैप तैयार करेगा। इसकी अध्यक्षता IIT बॉम्बे के प्रोफेसर एमेरिटस डी. बी. फाटक कर रहे हैं।
- Investor Education and Protection Fund Authority, under the Ministry of Corporate Affairs, in collaboration with the SEBI, will organise a 'Niveshak Shivar' in Bhubaneswar.
- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण, SEBI के सहयोग से भुवनेश्वर में एक 'निवेशक शिविर' का आयोजन करेगा।
- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has deployed an in-house Artificial Intelligence system named 'Sudarshan'.
- Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने 'Sudarshan' नाम का इन-हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम तैनात किया है।
- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) introduced major reforms in the ₹81 lakh crore Indian mutual fund industry.
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ₹81 लाख करोड़ के भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में बड़े सुधार किए हैं।





Ques: Gujarat has become the second state in India to pass the Uniform Civil Code (UCC) Bill. Which was the first state to implement UCC?

प्रश्न: गुजरात भारत का दूसरा राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित किया। UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था?

- A) Uttarakhand / उत्तराखंड
- B) Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश
- C) Himachal Pradesh / हिमाचल प्रदेश
- D) Maharashtra / महाराष्ट्र
- E) Goa / गोवा

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Gujarat has become the second state in India to pass the Uniform Civil Code (UCC) Bill.
- गुजरात भारत का दूसरा राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित किया है।
- Uttarakhand was the first state in India to implement the Uniform Civil Code (UCC).
- उत्तराखंड भारत का पहला राज्य था जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू किया।
- Uniform Civil Code (UCC) is a law that provides the same personal laws for all citizens, irrespective of religion.
- समान नागरिक संहिता (UCC) एक ऐसा कानून है जो सभी नागरिकों के लिए धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना समान व्यक्तिगत कानून प्रदान करता है।
- It covers areas like marriage, divorce, inheritance, and adoption, ensuring equality and uniformity in civil matters.
- यह विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को कवर करता है, जिससे नागरिक मामलों में समानता सुनिश्चित होती है।





Ques: What is the maximum accident insurance cover provided under PM Jan Dhan Yojana?

प्रश्न: पीएम जन धन योजना के तहत अधिकतम दुर्घटना बीमा कवर कितना है?

- A) ₹1 lakh / ₹1 लाख
- B) ₹2 lakh / ₹2 लाख
- C) ₹5 lakh / ₹5 लाख
- D) ₹10 lakh / ₹10 लाख
- E) ₹50,000 / ₹50,000

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is a flagship financial inclusion scheme of the Government of India.
- प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय समावेशन योजना है।
- The total balance under PMJDY has crossed ₹3 lakh crore, reaching ₹3,02,778 crore as of March 11.
- PMJDY के तहत कुल बैलेंस ₹3 लाख करोड़ से अधिक होकर 11 मार्च तक ₹3,02,778 करोड़ हो गया है।
- The scheme provides zero-balance bank accounts with no minimum balance requirement.
- इस योजना में जीरो बैलेंस बैंक खाते की सुविधा दी जाती है।
- Beneficiaries receive a free RuPay debit card with ₹2 lakh accident insurance cover.
- लाभार्थियों को ₹2 लाख दुर्घटना बीमा कवर के साथ मुफ्त RuPay डेबिट कार्ड मिलता है।
- An overdraft facility of up to ₹10,000 is available.
- इसमें ₹10,000 तक ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है।
- Deposits earn interest at the rate of 3% to 4%.
- जमा राशि पर 3% से 4% तक ब्याज मिलता है।

Static Facts | स्थिर तथ्य:

- Launch Date: 28 August 2014 / 28 अगस्त 2014
- Launched by: Government of India / भारत सरकार





Recent News Headlines Related to Schemes

- Directorate General of Foreign Trade under the Ministry of Commerce and Industry launched the RELIEF (Resilience and Logistics Intervention for Export Facilitation) scheme.
- विदेश व्यापार महानिदेशालय ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत RELIEF योजना शुरू की।
- K Ram Mohan Naidu announced the development of Arasavalli Sri Surya Narayana Swamy Temple under the PRASAD Scheme. The temple is located in Srikakulam, Andhra Pradesh. A foundation stone was laid for modernization of the Indrapushkarini temple tank with ₹24 crore sanctioned
- के. राम मोहन नायडू ने प्रसाद योजना के तहत अरसावल्ली श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर के विकास की घोषणा की। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में स्थित है। 24 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के साथ इंद्रपुष्करिणी मंदिर तालाब के आधुनिकीकरण के लिए आधारशिला रखी गई।
- Small Hydro Power Development Scheme has been approved by the Union Cabinet for the period FY 2026–27 to 2030–31 with an outlay of ₹22,584.60 crore.
- स्मॉल हाइड्रो पावर (SHP) विकास योजना को FY 2026–27 से 2030–31 तक ₹22,584.60 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी गई है।
- Bharat Audyogik Vikas Yojna (BHAVYA) has been approved by the Union Cabinet with an outlay of ₹33,660 crore.
- भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹33,660 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी है।
- The Andhra Pradesh government is set to launch a free bus travel scheme for differently abled persons under the “Divyang Shakti” scheme.
- आंध्र प्रदेश सरकार “दिव्यांग शक्ति” योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू करने जा रही है।
- The Chhattisgarh government has launched the “Gaudham Yojana” to promote cattle welfare and protection.
- छत्तीसगढ़ सरकार ने मवेशियों के कल्याण और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए “गौधाम योजना” शुरू की है।





Ques: As per NIRYAT data for FY 2024–25, which state emerged as the top textile-exporting state in India?

प्रश्न: FY 2024–25 के लिए NIRYAT डेटा के अनुसार भारत में शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य कौन सा रहा?

- A) Gujarat / गुजरात
- B) Maharashtra / महाराष्ट्र
- C) West Bengal / पश्चिम बंगाल
- D) Karnataka / कर्नाटक
- E) Tamil Nadu / तमिलनाडु

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Department for Promotion of Industry and Internal Trade under the Ministry of Commerce and Industry released the NIRYAT (National Import-Export Record for Yearly Analysis of Trade) data for FY 2024–25.
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत FY 2024–25 के लिए NIRYAT डेटा जारी किया।
- Tamil Nadu emerged as the top textile-exporting state with exports worth USD 7,997.17 million, accounting for 21.84% of India's total textile exports.
- तमिलनाडु शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य रहा, जिसका निर्यात USD 7,997.17 मिलियन (21.84%) रहा।
- India's total textile exports stood at USD 36,610 million in FY25.
- FY25 में भारत का कुल टेक्सटाइल निर्यात USD 36,610 मिलियन रहा।
- Other top exporting states include Gujarat (USD 5,646.01 million) and Maharashtra (USD 3,831.28 million).
- अन्य प्रमुख निर्यातक राज्यों में गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं।
- The NIRYAT portal, launched in 2022 by Narendra Modi, provides real-time comprehensive foreign trade data.
- NIRYAT पोर्टल, जिसे 2022 में नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया, रियल-टाइम विदेशी व्यापार डेटा प्रदान करता है।





Ques: The Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026 amends which Act?

प्रश्न: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 किस अधिनियम में संशोधन करता है?

- A) Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 / विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016
- B) Transgender Persons Act, 2019 / ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019
- C) Human Rights Act, 1993 / मानवाधिकार अधिनियम, 1993
- D) Juvenile Justice Act, 2015 / किशोर न्याय अधिनियम, 2015
- E) Equality Act, 2010 / समानता अधिनियम, 2010

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026 has been passed by the Parliament of India.
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है।
- It was approved by the Rajya Sabha after being passed by the Lok Sabha.
- यह बिल राज्यसभा द्वारा लोकसभा के बाद पारित किया गया।
- The Bill amends the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019.
- यह बिल ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है।
- The amendment redefines transgender identity and modifies certification procedures, shifting towards a biological (intersex-based) framework.
- संशोधन में ट्रांसजेंडर की परिभाषा और प्रमाणन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, जिसमें जैविक (इंटरसेक्स आधारित) ढांचे पर जोर दिया गया है।
- It introduces stricter punishments for offences, including imprisonment up to 14 years for serious crimes like forced labour or forced identity change.
- इसमें गंभीर अपराधों (जैसे जबरन मजदूरी या पहचान बदलने के लिए मजबूर करना) पर 14 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
- The Bill sparked political debate and demands for further scrutiny.
- इस बिल को लेकर राजनीतिक बहस और जांच की मांग भी उठी।





Static Facts | स्थिर तथ्य:

- Original Act Year: 2019
- मूल अधिनियम: 2019
- Ministry: Ministry of Social Justice and Empowerment
- मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय



EXAM
Genius





Ques: Exercise Kakadu 2026, in which INS Nilgiri participated, is hosted by which country's navy?

प्रश्न: एक्सरसाइज काकाडू 2026, जिसमें INS Nilgiri ने भाग लिया, किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया?

- A) India / भारत
- B) United States / अमेरिका
- C) Australia / ऑस्ट्रेलिया
- D) Japan / जापान
- E) United Kingdom / यूनाइटेड किंगडम

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- INS Nilgiri, an Indian Navy frigate, participated in the sea phase of Exercise Kakadu 2026 in Australia.
- आईएनएस नीलगिरी ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एक्सरसाइज काकाडू 2026 के समुद्री चरण में भाग लिया।
- Exercise Kakadu 2026 is the 17th edition of the multinational naval exercise.
- एक्सरसाइज काकाडू 2026 इस बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास का 17वां संस्करण है।
- The exercise is hosted by the Royal Australian Navy.
- यह अभ्यास रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी द्वारा आयोजित किया जाता है।
- It aims to enhance maritime cooperation, interoperability, and regional security among participating nations.
- इसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच समुद्री सहयोग, इंटरऑपरेबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है।





Recent News Headlines Related to Defence Exercise :

- The Indian Army's Southern Command conducted Exercise Amogh Jwala at the Babina Field Firing Ranges, Uttar Pradesh.
• भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में 'अमोघ ज्वाला' अभ्यास का संचालन किया।
- The Indian Navy participated in Exercise Sea Dragon 2026, a US-led multinational anti-submarine warfare exercise.
• भारतीय नौसेना ने Exercise Sea Dragon 2026 में भाग लिया, जो अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है।
- Exercise Cold Response 2026 was organised by the North Atlantic Treaty Organization (NATO).
• Exercise Cold Response 2026 का आयोजन North Atlantic Treaty Organization (NATO) द्वारा किया गया।
- Freedom Shield joint military exercise between the United States and South Korea is conducted across multiple military bases and training areas throughout South Korea.
• फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच दक्षिण कोरिया भर में कई सैन्य अड्डों और प्रशिक्षण क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है।
- An Indian Armed Forces contingent arrived in Seychelles to participate in the 11th edition of the joint military exercise 'Lamitiye 2026' with the Seychelles Defence Forces (SDF).
• भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल Seychelles पहुंचा, जहां वह Seychelles Defence Forces (SDF) के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास 'Lamitiye 2026' के 11वें संस्करण में भाग ले रहा है।
- The Southern Air Command of the Indian Air Force (IAF) successfully conducted a high-tempo joint maritime exercise named Kalari Leap in the Lakshadweep and Minicoy archipelago
• भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की दक्षिणी वायु कमान ने लक्षद्वीप और मिनिक्ॉय द्वीपसमूह में कलारी लीप नामक उच्च गति वाले संयुक्त समुद्री अभ्यास का सफलतापूर्वक संचालन किया।





Ques: NITI Aayog has sanctioned ₹1.55 crore for which centre in Andhra Pradesh?

प्रश्न: नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश में ₹1.55 करोड़ किस केंद्र के लिए स्वीकृत किए हैं?

- A) MSME Centre / एमएसएमई केंद्र
- B) RISE Centre / RISE केंद्र
- C) Startup India Hub / स्टार्टअप इंडिया हब
- D) Skill India Centre / स्किल इंडिया केंद्र
- E) Digital India Centre / डिजिटल इंडिया केंद्र

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- NITI Aayog has sanctioned ₹1.55 crore for the RISE Centre in Andhra Pradesh.
- नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश में RISE केंद्र के लिए ₹1.55 करोड़ की मंजूरी दी है।
- RISE stands for Rural Innovations, Incubation, Skilling and Entrepreneurship.
- RISE का पूर्ण रूप रूरल इनोवेशन्स, इन्क्यूबेशन, स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप है।
- The centre is located at Guntupalli in the NTR district.
- यह केंद्र गुंटुपल्ली में स्थित है।
- The initiative aims to empower rural women through development and entrepreneurship.
- इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को विकास और उद्यमिता के माध्यम से सशक्त बनाना है।
- Focus areas include AI-based skill training, infrastructure development, and entrepreneurship support.
- इसमें एआई आधारित स्किल प्रशिक्षण, अवसंरचना विकास और उद्यमिता सहायता शामिल है।
- The initiative aligns with the vision of “One Family–One Entrepreneur.”
- यह पहल “एक परिवार–एक उद्यमी” के विजन के अनुरूप है।

About NITI Aayog :

- Established: 1 January 2015 / 1 जनवरी 2015
- Headquarters: New Delhi / नई दिल्ली
- Chairperson: Prime Minister of India / भारत के प्रधानमंत्री





Ques: Under the 'Namo Drone Didi' scheme, what percentage of financial assistance is provided by the government for purchasing drones?

प्रश्न: 'नमो ड्रोन दीदी' योजना के तहत ड्रोन खरीदने पर सरकार द्वारा कितने प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है?

- A) 50%
- B) 60%
- C) 80%
- D) 90%
- E) 100 %

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

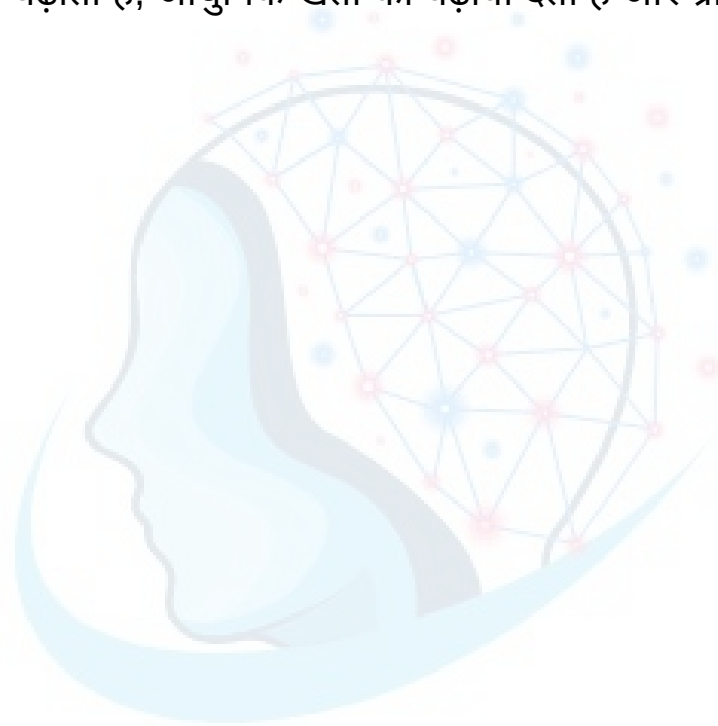
- The Government has approved the 'Namo Drone Didi' as a Central Sector Scheme to empower rural women.
- सरकार ने 'नमो ड्रोन दीदी' योजना को ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में स्वीकृत किया है।
- The scheme provides drones to Women Self Help Groups (SHGs) for rental agricultural services like spraying fertilizers and pesticides.
- इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ड्रोन दिए जाएंगे, ताकि वे किसानों को खाद और कीटनाशक छिड़काव जैसी सेवाएं किराये पर दे सकें।
- The government provides 80% Central Financial Assistance (CFA) on the cost of drones (including accessories), with a maximum limit of ₹8 lakh per SHG.
- सरकार ड्रोन की लागत (उपकरण सहित) का 80% वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹8 लाख प्रति SHG है।
- The remaining amount can be financed through loans via Cluster Level Federations (CLFs) under the Agriculture Infrastructure Fund with 3% interest subvention.
- शेष राशि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 3% ब्याज सब्सिडी के साथ CLFs द्वारा ऋण के रूप में ली जा सकती है।
- The drone package includes spray system, spare batteries, propellers, nozzle sets, and fast charger, along with 15 days training for pilot and assistant.
- ड्रोन पैकेज में स्प्रे सिस्टम, बैटरी, प्रोपेलर, नोजल सेट और चार्जर शामिल हैं, साथ ही पायलट व सहायक के





लिए 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है।

- Training is provided through Directorate General of Civil Aviation-authorized Remote Pilot Organisations (RPOs).
- प्रशिक्षण नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अधिकृत RPOs के माध्यम से दिया जाता है।
- The scheme improves agricultural productivity, promotes modern farming, and increases income opportunities for rural women.
- यह योजना कृषि उत्पादकता बढ़ाती है, आधुनिक खेती को बढ़ावा देती है और ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि करती है।



EXAM
Genius





Ques: The recent Herpes Simplex Virus (HSV) outbreak in Jalpaiguri Central Correctional Home occurred in which state?

प्रश्न: जलपाईगुड़ी सेंट्रल करेक्शनल होम में हाल ही में हुआ हरपीज सिंप्लेक्स वायरस (HSV) प्रकोप किस राज्य में हुआ?

- A) Bihar / बिहार
- B) West Bengal / पश्चिम बंगाल
- C) Odisha / ओडिशा
- D) Assam / असम
- E) Jharkhand / झारखंड

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The outbreak of Herpes Simplex Virus was reported in Jalpaiguri Central Correctional Home located in West Bengal.
- हरपीज सिंप्लेक्स वायरस का प्रकोप जलपाईगुड़ी सेंट्रल करेक्शनल होम में हुआ, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है।
- The incident has highlighted poor health conditions in Indian prisons, including overcrowding, lack of medical staff, and poor hygiene infrastructure.
- इस घटना ने भारतीय जेलों की खराब स्वास्थ्य स्थितियों को उजागर किया है, जैसे भीड़भाड़, चिकित्सा स्टाफ की कमी और खराब स्वच्छता व्यवस्था।
- According to National Crime Records Bureau (Prison Statistics India 2023), the national prison occupancy rate is 120.8%.
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार (Prison Statistics India 2023), राष्ट्रीय जेल अधिभोग दर 120.8% है।
- Some district jails reach 200–300% occupancy, indicating severe overcrowding.
- कुछ जिला जेलों में अधिभोग दर 200–300% तक पहुंच जाती है, जो अत्यधिक भीड़भाड़ को दर्शाता है।
- In West Bengal, prisons exceed 160% occupancy, with Kandi Sub-Jail historically crossing 400%.
- पश्चिम बंगाल में जेलों की अधिभोग दर 160% से अधिक है, जबकि कांडी सब-जेल में यह 400% तक पहुंच चुकी है।





Ques: The IVFRT scheme is related to which sector?

प्रश्न: IVFRT योजना किस क्षेत्र से संबंधित है?

- A) Agriculture / कृषि
- B) Banking / बैंकिंग
- C) Immigration & Visa Services / इमिग्रेशन एवं वीजा सेवाएं
- D) Education / शिक्षा
- E) Health / स्वास्थ्य

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Immigration Visa Foreigners Registration and Tracking Scheme has been extended for 5 years by the Union Cabinet of India.
- इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है।
- The scheme will run from 1 April 2026 to 31 March 2031 with a total outlay of ₹1800 crore.
- यह योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी, जिसका कुल बजट ₹1800 करोड़ है।
- IVFRT stands for Immigration, Visa, Foreigners Registration & Tracking.
- IVFRT का पूर्ण रूप इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एवं ट्रैकिंग है।
- It aims to modernise immigration and visa services in India.
- इसका उद्देश्य भारत में इमिग्रेशन और वीजा सेवाओं का आधुनिकीकरण करना है।
- The system enables 100% contactless visa processing with online appointment and payment facilities.
- यह प्रणाली 100% कॉन्टैक्टलेस वीजा प्रोसेसिंग तथा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और भुगतान सुविधा प्रदान करती है।
- Around 91% e-visa applications are processed within 72 hours.
- लगभग 91% ई-वीजा आवेदन 72 घंटे के भीतर प्रोसेस हो जाते हैं।

Static Facts | स्थिर तथ्य:

- Scheme Start Year: 2010 / 2010
- Ministry: Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय
- Type: E-Governance / Immigration System / ई-गवर्नेंस प्रणाली





Ques: Datta Meghe, who recently passed away, was associated with which field?

प्रश्न: हाल ही में निधन हुए दत्ता मेघे किस क्षेत्र से संबंधित थे?

- A) Politics / राजनीति
- B) Sports / खेल
- C) Science / विज्ञान
- D) Literature / साहित्य
- E) Business / व्यवसाय

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Datta Meghe was a veteran leader of the Bharatiya Janata Party and a former Member of Parliament.
- दत्ता मेघे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद थे।
- He was first elected as a Member of the Maharashtra Legislative Council in 1978 and served three consecutive terms till 1991.
- वह 1978 में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य चुने गए और 1991 तक लगातार तीन कार्यकाल तक रहे।
- He was a four-time Member of the Lok Sabha, representing constituencies like Nagpur, Ramtek, and Wardha.
- वह चार बार लोकसभा के सदस्य रहे, जिन्होंने नागपुर, रामटेक और वर्धा का प्रतिनिधित्व किया।
- He also served as a Member of the Rajya Sabha from 2002 to 2008.
- उन्होंने 2002 से 2008 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी सेवा दी।





Ques: The International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade is observed on which date?

प्रश्न: दासता और ट्रान्सअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?

- A) 20 March / 20 मार्च
- B) 22 March / 22 मार्च
- C) 23 March / 23 मार्च
- D) 25 March / 25 मार्च
- E) 27 March / 27 मार्च

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade is observed annually on 25 March.
- दासता और ट्रान्सअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 25 मार्च को मनाया जाता है।
- The date marks the passage of the Abolition of the Slave Trade Act 1807 in the United Kingdom.
- यह तिथि यूनाइटेड किंगडम में 1807 के दास व्यापार उन्मूलन अधिनियम 1807 के पारित होने की स्मृति में मनाई जाती है।
- Theme: "Justice in Action: Confronting History, Advancing Dignity, Empowering Futures"
- थीम: "Justice in Action: Confronting History, Advancing Dignity, Empowering Futures"
- The day aims to honor victims of slavery and promote awareness about the history and impact of the transatlantic slave trade.
- इस दिवस का उद्देश्य दासता के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देना और ट्रान्सअटलांटिक दास व्यापार के इतिहास व प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।





Ques: World Day of Theatre for Children and Young People is observed on which date?

प्रश्न: वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल किस तिथि को मनाया जाता है?

- A) 15 March / 15 मार्च
- B) 18 March / 18 मार्च
- C) 20 March / 20 मार्च
- D) 22 March / 22 मार्च
- E) 25 March / 25 मार्च

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- World Day of Theatre for Children and Young People is observed globally on 20 March every year.
- विश्व बाल एवं युवा रंगमंच दिवस हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है।
- The day aims to promote the cultural rights of children and youth.
- इस दिवस का उद्देश्य बच्चों और युवाओं के सांस्कृतिक अधिकारों को बढ़ावा देना है।
- It also highlights the importance of live theatre and performing arts in education and development.
- यह लाइव थिएटर और प्रदर्शन कला के महत्व को भी उजागर करता है, जो शिक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।





Important days :

- 1 March : Indian Bureau of Mines (IBM) celebrated its 79th Foundation Day as Khanij Diwas
- 1 March : Zero Discrimination Day (theme for 2026 was "People First")
- 1 March : World Seagrass Day
- 3 March : World Hearing Day (theme for 2026 is "From communities to classrooms: hearing care for all children.")
- 4 March : 18th World Day of Fight Against Sexual Exploitation 2026 (Started in 2009)
- 4 March : National Safety Day 2026 (Theme 2026 Engage, Educate & Empower People to Enhance Safety)
- 7 March : Jan Aushadhi Diwas
- 8 March : International Women's Day (Theme "Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls.")
- 10 March : CISF Raising Day
- 10 March : 5th International Day of Women Judges (Theme 2026 Women Judges on the Bench and Beyond: Protecting Access to Justice)
- 11 March (second Wednesday of March) : No Smoking Day 2026
- 12 March (second Thursday of March) : World Kidney Day (theme for 2026 was "Kidney Health for All: Caring for People, Protecting the Planet.")
- 14 March : Pi Day & International Day of Mathematics (Theme 2026 Mathematics and Hope)
- 14 March : 29th International Day of Action for Rivers Theme 2026 Protect Rivers, Protect People
- 15 March : International Day to Combat Islamophobia
- 15 March : World Consumer Rights Day (theme focuses on "Safe Products, Confident Consumers.")
- 16 March : National Vaccination Day (commemorates the launch of the Pulse Polio Programme in 1995)
- 18 March : 9th Global Recycling Day 2026 (Theme 2026 Don't Think Waste – Think Opportunity)
- 20 March : International Day of Happiness (theme for 2026 is "Caring and Sharing".) (first observed in 2013)





IMPORTANT ONE - LINER Current Affairs

The Manipur Government has launched the "Ningol Van Initiative" to strengthen forest conservation efforts and promote community participation.

Karnataka Grameena Bank was awarded the National Award for Outstanding Performance in Self-Help Groups (SHGs) Bank Linkage for 2024–25 by the Ministry of Rural Development. It was presented during the National Conference on Financial Literacy and Capacity Building and the 25th Central Level Coordination Committee meeting held in Hyderabad. It was launched by National Bank for Agriculture and Rural Development in 1992.

The next edition, Bharat Electricity Summit 2028, will be held in Gandhinagar, Gujarat.

The Summer Olympics 2028 (LA28) has revealed its official design and branding inspired by California's "Superbloom." The design is based on the Bird of Paradise flower, which is the official flower of Los Angeles. The 2028 edition will be the 34th Summer Olympics.

The Government has announced the launch of SHE (Self Help Entrepreneur) Marts to improve market access for women-led enterprises under the SHG ecosystem. The initiative will be implemented under Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission.

India has secured its position as the world leader in coconut production, contributing about 30.37% of the global output. A total of ₹350 crore has been allocated under "High-Value Agriculture" for coconut, cashew, and cocoa. Major coconut-producing states include Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, and West Bengal.





महत्वपूर्ण संक्षिप्त समाचार

मणिपुर सरकार ने वन संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए "निंगोल वन पहल" शुरू की है।

कर्नाटक ग्रामीण बैंक को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2024-25 के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के बैंक संपर्क में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार हैदराबाद में आयोजित वित्तीय साक्षरता और क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय सम्मेलन और 25वीं केंद्रीय स्तरीय समन्वय समिति की बैठक के दौरान प्रदान किया गया। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 1992 में की थी।

अगला संस्करण, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2028, गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया जाएगा।

ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 (एलए28) ने कैलिफोर्निया के "सुपरब्लूम" से प्रेरित अपना आधिकारिक डिज़ाइन और ब्रांडिंग जारी कर दिया है। यह डिज़ाइन बर्ड ऑफ पैराडाइज फूल पर आधारित है, जो लॉस एंजिल्स का आधिकारिक फूल है। 2028 का संस्करण 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा।

सरकार ने स्वयं सहायता उद्यम (एसएचजी) व्यवस्था के अंतर्गत महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए बाजार पहुंच में सुधार लाने हेतु एसएचई (स्वयं सहायता उद्यम) बाजारों के शुभारंभ की घोषणा की है। यह पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यान्वित की जाएगी।

भारत नारियल उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 30.37% का योगदान देता है। नारियल, काजू और कोको के लिए "उच्च मूल्य कृषि" के अंतर्गत कुल ₹350 करोड़ आवंटित किए गए हैं। प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।